ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-12* March-2021
Anthology : The Research

अस्थिर पर्यावरण के साथ आर्थिक विकास की बाधाएं
Barriers to Economic Development with A Volatile Environment

Paper Submission: 03/03/2021, Date of Acceptance: 24/03/2021, Date of Publication: 25/03/2021

तरुण जैन
सहायक आचार्य,
वाणिज्य विभाग,
डी0जे0कालेज, बड़ौत,
बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने के बाद लाख टके का सवाल यही है कि हम कैसे भूल सकते हैं कि जहां हमारा संविधान हमें कई तरह की आजादी देता है तो वही संविधान यह भी बताता है कि हमें – आपको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना ही पड़ेगा। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अपनी विद्युत आपूर्ति को पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन रहित करना चाहिए और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वनों में बढ़ोतरी करके कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना चाहिए । भारत का उद्देश्य विकास के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के खतरो से निपटने में योगदान करना है । इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम एक तरफ उत्सर्जन घटाने की कोशिश करें और दूसरी ओर वैकल्पिक ऊर्जा के भरपूर इस्तेमाल का भी प्रयास करें । जब अर्थव्यवस्था मे तेजी से वृद्धि की क्षमता विकसित होती हैं तो कई नई चुनौतियां भी आती हैं। हमे आर्थिक वृद्धि तथा निरंतर विकास के लिए यह निर्णय करना है कि दुर्लभतम संसाधनों का अनुकुलतम उपयोग कैसे होगा ।

After the second wave of corona epidemic, the question of lacquer is that how can we forget that while our constitution gives us many kinds of freedom, the same constitution also tells us that - you have to perform certain duties . According to the latest World Bank report, developing economies such as China and India should completely de-carbonate their power supply and increase carbon emissions by using carbon technology that curbs carbon emissions and curbs carbon emissions. India's objective is to contribute to the development as well as to deal with the threats of climate change. Achieving this goal is possible only when we try to reduce emissions on the one hand and on the other hand we also try to make full use of alternative energy. When the economy develops the capacity for rapid growth, many new challenges also arise. For economic growth and continuous development, we have to decide how optimal utilization of scarce resources will be.

मुख्य शब्द : पर्यावरण, आर्थिक वृद्धि, संसाधन, अर्थव्यवस्था, कोरोना।
Environment, Economic Growth, Natural Resources, Economics, CORONA.

प्रस्तावना

मानव के लिए पर्यावरण का अनुकूल और संतुलित होना बहुत जरूरी है। यदि हमने पर्यावरण संरक्षण पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाला मानव जीवन अंधकारमय हो जाएगा। आर्थिक पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना होगा। आर्थिक पर्यावरण को बचाये रख कर हम मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित कर सकते हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक वृद्धि में उचित संतुलन को स्पष्ट करने के लिए कायम रहने वाले विकास की धारणाओं का प्रयोग किया है इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से देश सतत् विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए भी प्रयासरत हैं अर्थात् विकास ऐसा होना चाहिए जो उत्पादन न घटाये और इसकी गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन लाए जिससे कि भावी पीढ़ी की क्षमताओं को बनाए रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। आर्थिक संवृद्धि तथा मानव विकास को अनुमानित करते समय पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण व ह्रास को सम्मिलित

करना आवश्यक है। मानव विकास रिपोर्ट 1996 केवल धारणीय विकास ही नहीं अपितु धारणीय मानव विकास पर जोर देती है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण अर्थात् औद्योगीकरण की तीव्रता से विश्व स्तर में पर्यावरण को बहुत ह्रास हुआ है और यह ह्रास स्थायी दिखलाई पड़ता है।

वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा तो भी हमारे संविधान अनुच्छेद 48 एवं 51 (जी0) से उद्धृत है। अनुच्छेद 48 (क) के अन्तर्गत वन्यखंड, प्रदूशण नियंत्रण, जल प्रबन्धन स्वच्छ उर्जा तथा समुद्री एवं तटीय पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न नीतिगत उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसलिए सभी लोगों को पर्यावरण का संरक्षण और देखभाल अवश्य करनी चाहिए क्योंकि जो औद्योगिक विकास की अनियंत्रित प्रगति में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के अधरूपतन के रूप में परिलक्षित हुआ है, वह बरबादी और नुकसान के रूप में हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ ही साथ भावी पीढ़ी को भी प्रभावित करेगा|

विश्व बैंक ने जून 2013 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2009 के लिए पर्यावरण ह्रास के जो अनुमान प्रकाशित किए उसके अनुसार भारत में पर्यावरण ह्रास जो सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत के बराबर व 3.75 लाख करोड़ रूपये थी। नीति निर्माताओं के लिए विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में नीति निर्धारित करना प्राकृतिक आपदाओं (बाद चक्रवात तूफान भू स्खलन इत्यादि) का अस्थिर मिश्रण निर्धनता एवं भूख की समस्या के साथ– साथ अनिश्चित मौसम स्वच्छ वायु. जल एवं ऊर्जा उपलब्ध कराए जाने का बड़ा दबाव चिंता का एक विषय है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप 1953–2009 के दौरान भारत को 2009 की कीमतों पर लगभग 15000 करोड़ रूपये की प्रतिवर्ष क्षति उठानी पड़ी है। इस दिशा में प्रो0 अमर्त्य सेन का यह कहना भी महत्त्वपूर्ण है कि हमें भारत में पर्यावरण की उपेक्षा तथा इसकी उपेक्षा के दुश्परिणामों को लेकर गंभीर चिंतन की पुरजोर आवश्यकता है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का लोगों के जीवन स्तर पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण भारत वर्तमान में 132 देशों में सबसे अधिक प्रदूषित है भारत की प्राकृतिक संपदा में 1990 से 2008 के बीच मूल्यानुसार 6 प्रतिशत की गिरावट (प्रति व्यक्ति आधार पर 30 प्रतिशत से अधिक) हुई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को बल देने वाली कमतर कार्बन वृद्धि रणनीतियों को रेखांकित किया है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दरों में गिरावट के बावजूद लगभग 7 अरब के पार पहुँच गई है और संसाधनों की अधिक मांग के साथ साथ शहरीकरण में वृद्धि भी जारी है। यह अनुमानित है कि 2031 में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2005 के प्रति व्यक्ति वैश्विक उत्सर्जन से कम हो होगा। 2011 में भारत की प्रति व्यक्ति (जी एच जी) वैश्विक हरित गृह गैस उत्सर्जन के अंदर ही होगा) समकक्ष जो कि 2005 के ब्द समकक्ष के 4.22 टन प्रति व्यक्ति वैर्वक उत्सर्जन से कम है।

विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयासों के साथ–साथ भारत यह भी जानता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का दबाव का खतरा उतना हो है। संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं जीविका कार्यक्रमों हेतु योजनाएँ पूर्णतया सार्थक हैं। महात् गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना भूमि, मृदा एवं जल से जुड़ी है। कृषि आधारित जीविका को बरकरार रखने के लिए मृदा की गुणवत्ता एवं उपजाऊपन को बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रम भी हैं ये योजनाएँ सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता को गतिशील एवं विकसित करने में मदद करती है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक अनवरत तरीके से किया जा सके तथा उनकी शक्तियों का और अधिक विकास किया जा सके।

पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के परम्परागत उपायों से इतर अतिरिक्त देखे जाने के पक्ष में तथा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से पहुँचे पर्यावरण क्षति पर ध्यान दिया गया है। भारत के लिए इस दिशा में ग्रीन नैशनल स्काउट्स हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रो0 दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह बनाया गया है।

पर्यावरण को समस्याओं के समाधान से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार करते हुए वैश्विक स्तर पर सहयोग, कार्यवाही एवं सूजनता की आवश्यकता है। 2012 में विश्व के माता जलवायु एवं पर्यावरण को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा जी–20 जैसे मच पर भी जहाँ अनवरत विकास एवं जलवायु परिवर्तन परिचर्चा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इन सभी भों पर होने वाली बातचीत में आम विषय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वाकाक्षी होना, विकासशील देशों में क्षमता निर्माण हेतु संस्थानों एवं तंत्रों तथा वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी का प्रावधान कर रहे हैं ।

वैश्विक सम्मेलनों में पर्यावरण एवं विकास के बीच अनुचित संतुलन ही एक विरोधाभास है। विकासशील देश गरीबी उन्मूलन के प्रति अनेक प्रयासों अथवा किसी महंगे करार में शामिल हों, ऐसी किसी बाध्यता में पड़ना नहीं चाहते हैं। नए धन और प्रौद्योगिकी की वचनबद्धताओं के बिना ग्रीन अर्थव्यवस्था और सतत् विकास संबंधी किन्हीं नए लक्ष्यों को पाना निरर्थक है।

जी–20, विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह, ने मैक्सिको की अध्यक्षता में 2011–12 के दौरान ग्रीन वृद्धि का एजेंडा अपनाया जी–20 एजेंडे में ग्रीन वृद्धि को शामिल करने का लक्ष्य था। विकासशील देशों विशेषकर कम आय वाले देशों को कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने में सहायता करना और साथ ही इन देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति और अधिक समपर्ति बनाने में समक्ष बनाना। वातावरण में कार्बन के संकेन्द्रण को उस सुरक्षित स्तर तक स्थायित्व देने के उद्देश्य से कार्बन और इसके तत्संगत वित्तपोषण स्कंधों के लिए वैश्विक बजट का विचार करना जिससे जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप से बचा जा सके। वैश्विक औसत तापमान में पहले ही 0.8°ब की वृद्धि हो चुकी है। यह व्यापक रूप से स्वीकारा गया है कि हम तेजी से तापमान में 2रूब की वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं

जिसके भीतर वैश्विक समुदाय अपने आप को सीमित करने का प्रयास कर रहा है।

भारत राजकोशीय उपकरणों और विनियामक हस्तक्षेपों के साथ बाजार तंत्रों के सावधानीपूर्वक मिश्रण का प्रयोग कर रहा है एक तरफ जहाँ कार्यले पर उपकर भारत में लगाए जा रहे कार्बन कर की एक किस्म है।

वहीं निष्पादन उपलब्धि और व्यापार (पी. ए.टी.) और वनीकरणीय खरीद दायित्व (आर. पी. ओ.) भारत में क्रमशः ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले कैंप और व्यापार बाजार तंत्रों के उदाहरण हैं। कार्बन कर राजस्व सहिक तब तक होता है जब अर्थव्यवस्था में अन्य कर दरों का कोई समायोजन इसमें शामिल न हो और यह राजस्व तटस्थ तब होता है जब अन्य कर दरों को समायोजित किया जाता है ताकि कार्बन कर से आने वाले राजस्व अन्तर्प्रवाह को कम किए गए करों से होने वाली आमदनी को समतुल्य कमी द्वारा पूर्णतः समायोजित किया जा सके।

कार्बन का प्रतिसंतुलन और इसके अपेक्षित वित्त पोषण के लिए वैश्विक प्रयास और प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। जो बाजार इसमें प्रचालनरत हैं वे अंतर्राष्ट्रीय बातचीत से संकेत प्राप्त करते हैं। अकेले घरेलू बाजार तंत्र न तो अपेक्षित है और न पैमाने पर संसाधनों को सृजित करने में पर्याप्त है और न ही लक्ष्यों के निर्धारित स्तर पर पुँचने इतने दक्ष है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय नीति एवं ढांचे पर अधिक निर्भर है।

प्राथमिक रूप से अपने ही सरोकारों में से भारत ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएँ और नीतियाँ बनाई हैं। जो इस वैश्विक जनकल्याण के प्रति भारत की प्रबल इच्छा को प्रतिबिंबित करती है तथापि प्रदत्त साधनों की कमी और प्रतिस्पर्धी माँगों के चलते संतुलनकारी संसाधनों को पाना काफी चुनौतिपूर्ण होगा। कम कार्बन रणनीतियों पर विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया है कि वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण दोनों के रूप में पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बिना अति उत्साहजनक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रियो–20 के शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में कहा था कि बहुत से देश और बेहतर कर सकते है । यदि उन्हें अतिरिक्त वित्त और प्रोद्योगिकी संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाए। दुर्भाग्य से इन क्षेत्रों में औद्योगिक देशों की ओर से पर्याप्त सहायता नहीं आती। कई विभिन्न कारणों से इस शताब्दी के अंत तक दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य पर लाया जाना चाहिए। यह विश्व की मजबूरी भी है और आवश्यकता भी।

विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को शताब्दी के मध्य तक अपनी विद्युत आपूर्ति को पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन रहित करना चाहिए और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने वाली प्रोद्योगिकी का उपयोग करके वनों में बढ़ोत्तरी करके कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना चाहिए परन्तु यह एक बड़ी चुनौती है जिसे जन कल्याण के हित में स्वीकार करना अपरिहार्य है।

भारत का उद्देश्य विकास के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में योगदान करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम एक तरफ उत्सर्जन घटाने की कोशिश करें और दूसरी ओर वैकिल्पक उर्जा के भरपूर इस्तेमाल का भी प्रयास करें। दुनिया को बचाने के लिए सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए ईमानदार व सकारात्मक प्रयास आवश्यक है। अमेरिका जैसे विकसित देश जो अपनी जीवन शैली बदलने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऊर्जा की खपत को कम नहीं करना चाहते हैं, और सभी प्रयत्न विकासशील देशों से करने की आशा करते हैं। साथ ही इन देशों पर अपनी शर्ते थोपना चाहते हैं। यदि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाना है तो ईमानदार प्रयास जरूरी है। भारत ने ऐसा प्रयास किया है और आज भी कर रहा है ।

अध्ययन का उद्देश्य

विश्व बैंक ने 18 अप्रैल 2015 को प्रदूषण प्रबंधन और पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम (पीएचईएम) का शुभारम्भ किया. इस कार्यक्रम का शुभारम्भ आधिकारिक तौर पर वाशिंगटन, डी.सी. में ग्लोबल सिटीजन 2015 अर्थ हे के अवसर पर किया गया। 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाला यह कार्यक्रम 2015 से 2020 तक चलेगा जिसमें तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण हवा की गुणवत्ता में बदलाव, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों किये किये जाने वाले उपाय तथा पानी और भूमि प्रदूषण से निपटने के कार्यक्रम भी शामिल होंगे इसके तहत पांच प्रमुख शहरी क्षेत्रों भारत, चीन, मिस, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में हवा की गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा।

निष्कर्ष

भारत में भूरक्षण भी एक बड़ी समस्या है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 प्रतिशत की कमी हो जाती है। इससे फसल के अंदर पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। जमीन को संरक्षण करना बहुत आसान है। घास उगाकर, पेह लगाकर, झाइयों उगाकर यह क्षरण रोका जा सकता है। उर्वरकों का इस्तेमाल खत्म करना आज की आवश्यकता है। उक्त छोटे छोटे उपाय करके भी पर्यावरण को बहुत बड़ी हद तक सुधारा जा सकता है।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बजाय सतत एवं स्थिर विकास को आर्थिक विकास का पैसाना बनाया जाना चाहिए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का भंडार बरकरार रखा जा सके। साथ ही, रीसाइकलिंग उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होगे। पूरी दुनिया में उपज का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है।

भारत में भी यही स्थिति है। इन फसलों को उगाने में बडी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, पानी का

बहुत अधिक उपयोग होता है, परिवहन की लागत लगती है। अतः अनाज और खाद्य पदार्थी की बौदी रोकना भी पर्यावरण संरक्षण का काम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *World Bank, World Development Report-2010-2020 (Washington DC, 2020).*
2. *Puran Mongia "Environment Policy," The New Oxford Compenion to Economics in India, New Delhi*
3. *आर्थिक समीक्षा*
4. *WHO,(2009) "Environmental burden of cliseares Country profile." WHO.*
5. *Keiser D, Shapiro J (2019) Consequences of the Clean water Ad and the demand quality. QJ Econ 134: 349 – 396 for water quality. QJ Econ 134:349-396*
6. *Lemoine D, Rudik I (2017). Annu Rev Resaur Econ 9: 117-142.Econ 9:117-142*